भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.04.2022 के
तारांकित प्रश्न सं. 491 का उत्तर

रेलवे के विकास कार्यों को पूरा किया जाना

***491 श्री सुनील बाबूराव मेंढेः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गोंदिया-भंडारा में नागपुर-बिलासपुर (तीसरे चरण के अंतर्गत) रेल लाइन के संबंध में विभिन्न विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

रेलवे के विकास कार्यों को पूरा किए जाने के संबंध में दिनांक 06.04.2022 को लोक सभा में श्री सुनील बाबूराव मेंढे के तारांकित प्रश्न सं. 491 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेलवे ने 2015-16 के बजट में शामिल राजनंदगांव-नागपुर (कलुमना) तीसरी लाइन (228.30 कि.मी.) परियोजना के एक हिस्से के रूप में गोंदिया-भंडारा रेल लाइन के तिहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। परियोजना की प्रत्याशित लागत 3,177 करोड़ रु. है। अभी तक, 1674 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और इस परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है।

इस परियोजना में 23.95 हैक्टेयर राजस्व भूमि का अधिग्रहण और छत्तीसगढ़ में 20.95 हैक्टेयर भूमि की वन संबंधी मंजूरी शामिल है। छत्तीसगढ़ में संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण और वन संबंधी स्वीकृति का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में इस परियोजना में 44.72 हैक्टेयर राजस्व भूमि का अधिग्रहण और 35.43 हैक्टेयर भूमि की वन संबंधी मंजूरी शामिल है। इसमें से 37.80 हैक्टेयर राजस्व भूमि और 1.24 हैक्टेयर भूमि की वन संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। महाराष्ट्र में 6.92 हैक्टेयर शेष राजस्व भूमि का भूमि अधिग्रहण और 34.19 हैक्टेयर भूमि की वन संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

राजनंदगांव-डोंगरगढ़ (31.20 किमी), डोंगरगढ़-पनियाजोब (8 किमी), बोरतलाव-दाराकसा (9.20 किमी) और तुमसर-भंडारा (18.26 किमी) का कार्य पूरा कर दिया गया है। उपलब्ध भूमि में शेष खंडों में कार्य शुरू कर दिया गया है।

किसी भी रेल परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत हिस्सेदारी परियोजनाओं में संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा लागत हिस्सेदारी का जमाव बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की

संख्या और ये सभी कारक परियोजना की समापन लागत को प्रभावित करते हैं। फिर भी, भारतीय रेल द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

2014 के बाद से, बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का कार्य तदनुरूप पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2014-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन 2009-14 के दौरान 311 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2,274 करोड़ रुपये प्रति वर्ष किया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 631% अधिक है। इन परियोजनाओं के लिए बजट परिव्यय को 2019-20 में बढ़ाकर 3,269 करोड़ रुपये (2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट परिव्यय से 951% अधिक) और वित्त वर्ष 2020-21 में 3874 करोड़ रुपये (2009-14 के औसत वार्षिक बजट आवंटन से 1146% अधिक) किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, इन कार्यों हेतु 3730 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय मुहैया कराया गया है जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग से 1099% अधिक है।

वर्ष 2014-21 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 637 किमी के खंडों (132 कि.मी नई लाइन और 505 कि.मी दोहरीकरण) को 91 किमी प्रति वर्ष के औसत दर से पूरा किया गया है, जो वर्ष 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग (6.4 कि.मी. प्रति वर्ष) से 1322% अधिक है।

*****